## भारत और मालदीव के रिश्ते फिर पटरी पर

## उत्तराखंड योग की वैश्विक राजधानी बनने की राह पर: दीपेन्द्र चौधरी


# दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

वर्ष 15 | अंक 10 | मूल्य 15 रुपये | 27 जुलाई-02 अगस्त, 2025


# संवैधानिक पद की 'ऊंची कुर्सी' अचानक खाली हो गई

# 5th TOPPERS' CONCLAVE

## Award Ceremony of Meritorious Students & 25 Best Schools of Dehradun

DEHRADUN'S 25 BEST SCHOOLS 2025

Powered By

**Will Live Again**

Powered By

on Saturday, 2nd August, 2025

वर्ष 15 | अंक 10

# दिव्य हिमगिरि

27 जुलाई-02 अगस्त, 2025

**संपादक**
कुँवर राज अस्थाना

**वरिष्ठ संवाददाता**
शंभूनाथ गौतम

**विज्ञापन**
पूनम आर्या

**ग्राफिक डिजायनर**
देव भट्ट

**संवाददाता**
**हरिद्वार:** डॉ. रजनीश गौतम
**पौडी:** रत्नमणि भट्ट
**कोटद्वार:** के.पी. बौंठियाल
**रूद्रपुर:** हेमचन्द्र बुडलाकोटी
**चमोली:** मुकेश रावत
**रुड़की:** श्रीगोपाल नारसन
**नैनीताल:** शीतल तिवारी
**अल्मोड़ा:** संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
**विकासनगर:** अजय शर्मा
**प्रसार:** रमेश सिंह रावत

**संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)**
**मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164**
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित। संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

## नस्लीय कुंठाओं में डूबे विकसित देश

यह विचित्र विडंबना है कि जिस दौर में विश्वभर में किसी समाज के विकास को आधुनिकता के आईने में देखने की अपेक्षा की जाती है, उसमें कई बार कुछ घटनाएं इस कसौटी पर बहुस्तरीय नाकामी को रेखांकित करती हैं। ऐसी सामाजिक प्रवृत्तियों का सिरा ढूंढ़ना मुश्किल हो जाता है, जिसमें एक ओर कोई समाज सभ्यता के मानदंडों पर अन्य के मुकाबले अपने श्रेष्ठ होने का दंभ भरे, लेकिन वहीं कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा भी हो जो उनके दुराग्रहों और कुंठाओं से भरे होने का सूचक हो। गौरतलब है कि आस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक हिंदू मंदिर और दो एशियाई रेस्तरां की दीवारों को नस्लवादी भित्तिचित्रों से विकृत कर दिया गया और नस्ली नफरत फैलाने वाली बातें लिखी गईं। खबर के मुताबिक, स्थानीय पुलिस ने इस घटना की पुष्टि जरूर की और कहा कि हमारे समाज में घृणा आधारित और नस्लवादी व्यवहार के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। यानी जिन लोगों ने नस्ली नफरत फैलाने की कोशिश की, उन्हें स्थानीय स्तर पर कोई व्यापक समर्थन नहीं है। इसके बावजूद अक्सर ऐसी घटनाएं होते रहने की खबरें बताती हैं कि वहां ऐसे तत्त्व भी हैं, जो आस्ट्रेलिया की सामाजिक विकास नीतियों में मौजूद कमियों के सूचक हैं। भारतीय और एशियाई पहचान के लोगों को लक्ष्य बना कर मेलबर्न में इस तरह नस्लीय दुराग्रहों का प्रदर्शन कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से आस्ट्रेलिया में ही इसी प्रकृति की कई घटनाएं सामने आईं। इसके अलावा, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, न्यूजीलैंड और अन्य कुछ देशों में भी भारतीय पहचान के लोगों पर नस्ली हमले हुए, घृणा से भरी टिप्पणियां की गईं और प्रत्यक्ष रूप से अपमानित करने की कोशिश की गई। ऐसे अनेक वाकये हैं, जिनमें किसी व्यक्ति ने बिना किसी कारण के सिर्फ भारतीय पहचान के आधार पर जानलेवा हमला किया। सवाल है कि ऐसी आक्रामकता का स्रोत क्या है? आखिर क्या वजह है कि हाल के वर्षों में अलग-अलग देशों में भारतीयों के प्रति इस तरह के हमलों में इजाफा हुआ है? जिस दौर में भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अहम मुद्दों के मामले में अपना मजबूत दखल देता दिख रहा है, उसमें भारतीय लोगों और उनकी आस्था को चोट पहुंचाने की घटनाओं पर बात सिर्फ चिंता जाहिर करने तक क्यों सिमट कर रह जाती है? क्या इसे कूटनीतिक मोर्चे पर एक नाकामी के तौर पर देखा जाएगा कि संबंधित देशों की सरकारें अपने यहां भारतीयों के प्रति नस्लवादी नफरत फैलाने वाले तत्त्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करतीं और इसीलिए ऐसी घटनाएं होती रहती हैं? यह समझना मुश्किल है कि जिन देशों को वैश्विक स्तर पर विकसित देशों की श्रेणी में माना जाता है, वहां इस तरह की स्थिति क्यों बनी हुई है, जिसमें कुछ लोग नस्लवादी पूर्वाग्रहों से भरे हुए हैं और किसी अन्य पहचान वाले लोगों या समुदायों को कमतर मान कर उनके साथ अमानवीय तरीके से पेश आते हैं। सवाल है कि प्रतिगामी धारणाओं या मनोग्रंथियों से भरा हुआ कोई व्यक्ति या समाज सभ्य और आधुनिक होने की कसौटी पर खुद को किसी से श्रेष्ठ कैसे मान सकता है। दरअसल, नस्लवादी दुराग्रहों से भरे हुए कुछ लोग इस पहलू पर विचार करने की भी कोशिश नहीं करते और उनकी हरकतों से उपजे सवालों का जवाब दूसरे लोगों को देना पड़ता है। नस्लीय कुंठाओं में डूबे रहने के नतीजे में किसी व्यक्ति या समूह के भीतर जिस तरह की आक्रामकता और हिंसा का विस्तार होता है, उसका खमियाजा एक साथ कई पक्षों को भुगतना पड़ता है।

**कुँवर राज अस्थाना**

# उत्तराखंड योग की वैश्विक राजधानी बनने की राह पर: दीपेन्द्र चौधरी

**'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट विजन है- योग को सिर्फ भारत की पहचान नहीं, बल्कि विश्व मानवता के लिए समाधान बनाना है। उत्तराखंड इसी संकल्प को जमीन पर उतार रहा है।' पेश है उत्तराखंड शासन में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के सचिव दीपेन्द्र चौधरी, आईएएस से विशेष बातचीत**

**प्रश्नः इस वर्ष योग दिवस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा भराड़ीसैंड में देश की प्रथम योग नीति के लागू करने की घोषणा की गई। योग योग नीति 2025 को लेकर सबसे पहली बात यही जानना चाहेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?**

**उत्तरः** देवभूमि उत्तराखंड योग और आयुर्वेद की पावन भूमि रही है। यह वही धरती है जहां प्राचीन ऋषि-मुनियों ने योग की गूढ़ साधनाओं को जन्म दिया और ध्यान की परंपरा को प्रवाहित किया। इसके बावजूद, राज्य में लंबे समय तक योग को किसी नीति आधारित दिशा या संस्थागत प्रोत्साहन का अभाव रहा।

जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योग को वैश्विक मंच पर पहचान और गौरव प्राप्त हुआ, तब यह आवश्यक हो गया कि उत्तराखंड- जो योग की जन्मभूमि माना जाता है- भी अपनी सांस्कृतिक, आध्यत्मिक और आर्थिक भूमिका का निर्वहन करते हुए एक ठोस नीति लेकर आगे आए। इसी उद्देश्य को लेकर, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में ''उत्तराखंड योग नीति 2025'' की घोषणा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर भराड़ीसैंण से की गई। इस नीति की आवश्यकता कई स्तरों पर स्पष्ट रूप से अनुभव की गई। राज्य में वर्तमान में सैकड़ों योग केंद्र वर्षों से बिना किसी सरकारी पंजीकरण, मानकीकरण या निगरानी के स्वतंत्र रूप से संचालित हो रहे थे, जिससे योग सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। योग शिक्षा के क्षेत्र में भी मानकीकृत पाठयक्रम की अनुपस्थिति एक गंभीर चुनौती बनी हुई थी- विभिन्न संस्थाएं अपने-अपने पाठयक्रम चला रही थीं, जिससे योग शिक्षा में न तो एकरूपता रही और न ही गुणवत्ता की कोई गारंटी। इससे प्रशिक्षुओं की योग्यता का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना कठिन हो गया था। ऋषिकेश में कई अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त योग स्थलों में विदेशी प्रमाणन एजेंसियां स्थानीय योग केंद्रों को प्रमाणित कर रही थीं, जबकि भारत सरकार के Yoga Certification Board (YCB) को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल पा रही थी। यह न केवल राष्ट्रीय मानकों की अनदेखी थी, बल्कि भारत की पारंपरिक योग परंपरा की आत्मनिर्भरता को भी प्रभावित कर रहा था। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के अनेक क्षेत्रों- विशेषकर पर्वतीय जिलों- में योग, वेलनेस और पंचकर्म पर्यटन की अपार संभावनाएं होते हुए भी अब तक कोई ठोस नीति इन संभावनाओं को स्थायी योग केंद्रों (Yoga Hubs) के रूप में विकसित करने हेतु मार्गदर्शन और सहयोग नहीं दे पा रही थी। इन क्षेत्रों में भूमि, प्रशिक्षण, प्रमाणन, निवेश और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं को संस्थागत समर्थन देने के लिए एक समर्पित नीति की नितांत आवश्यकता थी।

उत्तराखंड योग नीति 2025 उपरोक्त सभी चुनौतियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। यह नीति राज्य में योग के नियमन, मानकीकरण, प्रमाणन, शोध, प्रशिक्षण, रोजगार सृजन और वेलनेस पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम है। इससे न केवल योग की गरिमा और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, बल्कि उत्तराखंड को 'आयुष और योग राज्य' के रूप में वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित करने में भी अभूतपूर्व सहायता मिलेगी।

**प्रश्नः इस योग नीति का मूल उद्देश्य क्या है?**

**उत्तरः** इस योग नीति का मूल उद्देश्य है- उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करना। यह केवल एक घोषणात्मक या भावनात्मक सपना नहीं, बल्कि ठोस रणनीतियों, लक्षित योजनाओं और दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिबद्धताओं से जुड़ा एक सुविचारित मिशन है।

इस नीति के माध्यम से योग को केवल साधाना या व्यक्तिगत कल्याण तक सीमित न रखकर उसे शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और आर्थिक विकास से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत योग से संबंधित पाठयक्रमों के मानकीकरण, प्रशिक्षकों के प्रमाणन, युवाओं के लिए रोजगारोन्मुख अवसरों के सृजन, और ग्रामीण क्षेत्रों में वेलनेस हब्स के विकास का स्पष्ट खाका प्रस्तुत किया गया है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा

एक पृथक 'योग निदेशालय' की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है, जो नीति के सभी पहलुओं की निगरानी, समन्वय एवं गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करेगा।

**प्रश्नः नीति में क्या ठोस लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?**

**उत्तरः** उत्तराखंड योग नीति 2025 में कई स्पष्ट और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इनमें वर्ष 2030 तक प्रदेश में पाँच अंतरराष्ट्रीय स्तर के योग हब स्थापित करना, वर्ष 2026 तक सभी आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में योग प्रशिक्षक उपलब्ध कराना, दिसंबर 2025 तक सभी योग संस्थानों का पंजीकरण सुनिश्चित करना तथा मार्च 2026 तक उत्तराखंड का अपना ऑनलाइन योग और ध्यान प्लेटफॉर्म प्रारंभ करना शामिल है। इन लक्ष्यों के माध्यम से योग को संगठित रूप में जनसामान्य तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।

**प्रश्नः ये योग हब कहां और कैसे स्थापित किए जा रहे हैं?**

**उत्तरः** योग नीति 2025 के अंतर्गत 'योग हब' को ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ न्यूनतम 80-100 व्यक्तियों को मुख्य रूप से योग और ध्यान सेवाओं से जुड़ा रोजगार प्राप्त हो। इन सेवाओं में योग केन्द्रों के संचालन, प्रशिक्षण सुविधाओं, वर्कशॉप एवं समुदाय आधारित योग गतिविधियों, वेलनेस रिट्रीट्स, स्पा सेवाएं आदि सम्मिलित हैं। **हमने 5 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है:** 1. जागेश्वर 2. मुक्तेश्वर 3. पिथौरागढ़ की व्यास, दारमा और चौंदास वैली 4. टिहरी झील क्षेत्र 5. चम्पावत का कोली ढेक झील क्षेत्र

**प्रश्नः क्या सरकार इन योग हब के लिए आर्थिक सहायता भी दे रही है?**

**उत्तरः** हां, उत्तराखंड सरकार योग हब्स के विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में 20 लाख और मैदानी क्षेत्रों में 10 लाख तक की सब्सिडी तीन किस्तों में दी जाएगी।

**प्रश्नः रोजगार की दृष्टि से इस नीति का कितना प्रभाव होगा?**

**उत्तरः** नीति पूरी तरह रोजगार केंद्रित है। इस नीति से 13,000 से अधिक व्यक्ति लाभान्वित होंगे। 2,500 से अधिक योग शिक्षक प्रमाणित होंगे और 10,000 से अधिक प्रशिक्षक होमस्टे, रिसॉर्ट्स तथा अन्य संस्थानों में रोजगार पाएंगे इससे न केवल शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे, बल्कि स्थानीय युवाओं की आजीविका भी मजबूत होगी।

**प्रश्नः योग शिक्षकों को क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है?**

**उत्तरः** योग सर्टिफिकेशन बोर्ड (YCB) की परीक्षा में सफल प्रशिक्षकों को परीक्षा शुल्क का प्रतिपूर्ति मिलेगा। प्रति वर्ष लगभग 500 शिक्षकों को लाभ प्रदान किया जाएगा.

**प्रश्नः स्कूल और कॉलेज के छात्र भी इसका लाभ ले पाएंगे क्या?**

**उत्तरः** बिलकुल। हम योग को शिक्षा के पाठयक्रम में शामिल कर रहे हैं। विद्यालयों में नियमित योग सत्र होंगे और छात्र योग को करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए भी प्रेरित होंगे।

**प्रश्नः रिसर्च और नवाचार के लिए क्या प्रावधान हैं?**

**उत्तरः** हर योग-आधारित अनुसंधान परियोजना को 10 लाख तक का अनुदान मिलेगा। और नीति के अंतर्गत कुल 1 करोड़ का अनुसंधान बजट निर्धारित किया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय, मेडिकल संस्थान के साथ साथ गैर-सरकारी संगठन भी पात्र होंगे।

**प्रश्नः छोटे होटलों और होमस्टे को क्या लाभ होगा?**

**उत्तरः** नीति के अंतर्गत होम स्टे, होटल, रिसोर्ट में योग सेवाएँ उपलब्ध कराए जाने को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। यदि कोई होटल, रिसॉर्ट आदि प्रमाणित योग प्रशिक्षक के माध्यम से योग सत्र संचालित करता है, तो तीन महीने तक उसे 250 प्रति घंटा की दर से 20 घंटे प्रतिमाह तक प्रतिपूर्ति दी जाएगी।

**प्रश्नः महिलाओं और युवाओं के लिए क्या विशेष अवसर हैं?**

**उत्तरः** यह नीति महिलाओं के लिए घर बैठे स्वरोजगार का सबसे सहज माध्यम बन सकती है। वे योग सर्टिफिकेशन बोर्ड से प्रमाणन प्राप्त कर डिजिटल योग सत्र संचालित कर सकती हैं या गांव में सेंटर खोल सकती हैं। होम स्टे संचालक महिलाएं स्वयं या ग्राम की किसी अन्य योग प्रशिक्षक महिला को नियोजित कर योग सेवायें प्रदान कर सकती हैं ।

**प्रश्नः नीति की निगरानी और संचालन के लिए क्या व्यवस्था है?**

**उत्तरः** योग नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयुष विभाग के अन्तर्गत ही नया योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय स्थापित किया जा रहा है, जो नीति के हर पहलू यानि केंद्रों के पंजीकरण, प्रमाणन, गुणवत्ता मानक, सब्सिडी वितरण, निगरानी आदि पर काम करेगा।

**प्रश्नः क्या योग संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन भी किया जाएगा?**

**उत्तरः** हां। इसके लिए 'स्टार रेटिंग सिस्टम' लागू किया जा रहा है तथा एक पोर्टल तैयार किया जाएगा जिससे योग संस्थान पारदर्शिता और गुणवत्ता के आधार पर मूल्यांकित होंगे।

**प्रश्नः क्या कोई पंजीकरण प्रणाली भी अनिवार्य की गई है?**

**उत्तर'** हर योग संस्थान को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और नीति के विभिन्न प्रविधानों के लिए योग सर्टिफिकेशन बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। पंजीकरण के लिए अलग से योग निदेशालय को स्थापित किया जा रहा है ।

उत्तराखंड योग नीति 2025 के लिए आगामी पाँच वर्षों हेतु कुल 35.31 करोड़ का अनुमानित बजटीय प्रावधान रखा गया है, जिसे नीति की वार्षिक समीक्षा के आधार पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। इस बजट में योग एवं ध्यान केंद्रों की स्थापना हेतु 25 करोड़, शोध कार्यो के लिए 1 करोड़, योग प्रमाणन हेतु 1.81 करोड़, तथा योग सत्रों के संचालन व प्रोत्साहन हेतु 7.5 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

**प्रश्नः वैश्विक स्तर पर योग को पहुंचाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं?**

**उत्तरः** नीति के अंतर्गत 15-20 प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय योग संस्थानों के साथ MoU किया जाएगा, जिससे शोध, शिक्षा और रोजगार के वैश्विक अवसर उत्पन्न होंगे। राज्य में प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय योग कार्यक्रम और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विश्व भर के योग विशेषज्ञ, साधक और शोधकर्ता भाग लेंगे। यह उत्तराखंड को अंतरराष्ट्रीय योग समुदाय से जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम

बनेगा।

**प्रश्नः पर्यटन को इससे कैसे जोड़ा जा रहा है?**

**उत्तरः** प्रदेश को वैश्विक योग राजधानी के रूप में विकसित करने हेतु आयुष एवं पर्यटन विभाग को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। प्रदेश के होमस्टे में योग को अनिवार्य बनाते हुए इन्हें वेलनेस स्टे के रूप में विकसित किया जाएगा। विदेशों में योग सीखने, ध्यान के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने और आध्यात्म से जुड़ने की बढ़ती रुचि को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड को वेलनेस पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। वर्तमान में करोड़ों पर्यटक उत्तराखंड आते हैं, किंतु उनकी ठहरने की अवधि कम होती है- योग एवं वेलनेस से जोड़कर इस अवधि को 1-2 सप्ताह तक बढ़ाया जा सकता है।

**प्रश्नः क्या इसमें प्रदेश की जनता से भी कोई सहयोग अपेक्षित है?**

**उत्तरः** हाँ, उत्तराखंड योग नीति 2025 के सफल क्रियान्वयन में प्रदेश की जनता की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग को जन-जन तक पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक स्वयं योग को अपनी जीवनशैली में अपनाएँ, अपने बच्चों को विद्यालयों में योग गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, और स्थानीय स्तर पर योग केंद्रों व कार्यक्रमों से जुड़ें। होमस्टे, स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थानों में योग सत्रों को बढ़ावा देकर जनता इस नीति को धरातल पर सशक्त बना सकती है। जनसहयोग से ही उत्तराखंड को वैश्विक योग राजधानी बनाया जा सकता है।

**प्रश्नः अंत में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?**

**उत्तरः** अंत में मैं प्रदेश की जनता से यही आग्रह करना चाहूंगा कि वे योग को केवल उत्सव का विषय न मानकर दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। योग से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन और विचार भी संतुलित होते हैं, जिससे समाज में शांति और सकारात्मकता आती है। मैं विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए प्रेरणादायक संदेश- 'हर घर योग, हर जन निरोग' को आत्मसात करने का अनुरोध करता हूँ।

आइए, इस संदेश को घर-घर पहुंचाएं और मिलकर उत्तराखंड को योग, स्वास्थ्य और अध्यात्म की विश्व राजधानी बनाएं।

उत्तराखण्ड शासन
देवभूमि रजत उत्सव

1916—1944

25 जुलाई

स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रदूत
अमर शहीद
श्रीदेव सुमन
को उनकी पुण्यतिथि पर
उत्तराखण्डवासियों की ओर से
शत्-शत् नमन

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी
www.uttarainformation.gov.in | DIPR_UK | UttarakhandDIPR | UttarakhandDIPR

# भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता: एक क्रांतिकारी कदम

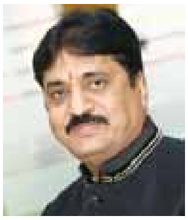

ललित गर्ग

भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की अंतिम स्वीकृति ने न केवल वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मचा दी है, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य को भी एक नई दिशा दी है। दोनों देशों के बीच आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने का फायदा दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से संरक्षणावाद बढ़ा है, उसमें ऐसे व्यापार समझौतों की भूमिका और भी अहम हो जाती है। इस समझौते से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल अमेरिका बल्कि अन्य देशों को भी भारत की मजबूत होती स्थिति का आइना दिखाया है, जो उनकी दूरगामी एवं कूटनीतिज्ञ राजनीति का द्योतक है। इस समझौते को मौजूदा दौर में दुनियाभर में जारी बहुस्तरीय तनाव, दबाव एवं दादागिरी की राजनीति के बीच एक बेहतर एवं सूझबूझभरी कूटनीतिक कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। यह छिपा नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने शुल्क के मोर्चे पर एक बड़ा द्वंद्व एवं संकट खड़ा कर दिया था। लेकिन भारत ने इस द्वंद्व के बीच झुकने की बजाय नये रास्ते खोजे हैं। निश्चित ही यह व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) महज एक कागजी करार नहीं, बल्कि 'विकसित भारत 2047' के स्वप्न को मूर्त रूप देने की ठोस रणनीति है। जहां एक ओर यह समझौता 99 प्रतिशत टैरिफ को समाप्त कर वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, कृषि व रत्न-आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को नई उड़ान देगा, वहीं दूसरी ओर छोटे उद्यमों, मछुआरों और किसानों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाएगा। भारत के ग्रामीण अंचलों से हल्दी, दाल, अचार जैसे उत्पाद अब ब्रिटिश बाजारों में अपनी महक फैलाएंगे।

मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में जिस प्रकार से गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता पर जोर दिया, उसी का परिणाम है यह करार। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि अब भारत केवल बाजार नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है, जो अपने हितों की रक्षा करते हुए विश्व से संवाद करता है। यह समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, यह सेवा क्षेत्र, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, निवेश, सामाजिक सुरक्षा, और दोहरे कराधान जैसे क्षेत्रों में भी भारतीयों के लिए नए दरवाजे खोलता है। खासकर ब्रिटेन में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के लिए यह राहत का संदेश है, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिल सकेगी। यह समझौता इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि अब तक अमेरिका की ओर से पैदा किये गये किसी दबाव के आगे भारत ने झुकना स्वीकार नहीं किया और उसने भारत-ब्रिटेन जैसे नये विकल्पों को खड़ा करने और पुराने को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाये हैं।

ब्रिटेन के साथ यह एफटीए एक उदाहरण है कि कैसे भारत न्यायसंगत और समावेशी व्यापार समझौते कर सकता है, जिसमें न तो अपने किसानों, न ही डेयरी क्षेत्र या छोटे उत्पादकों को नुकसान होता है। भारत ने संवेदनशील क्षेत्रों को समझौते से बाहर रखकर आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा की अपनी नीति को बरकरार रखा है। वर्तमान में भारत का वैश्विक व्यापार लगभग 21 अरब डॉलर है, जो इस समझौते के बाद 2030 तक 120 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना रखता है। यह न केवल विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग हिस्सेदारी को 17 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बढ़ाने में सहायक होगा। इस करार के साथ, मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि जब नियोजित दृष्टिकोण, वैश्विक प्रतिष्ठा और साहसिक निर्णय साथ चलते हैं, तो भारत जैसे विकासशील देश भी वैश्विक मंच पर निर्णायक बन सकते हैं।

भारत और ब्रिटेन के बीच सीईटीए के अस्तित्व में आने से एक नये आर्थिक सूर्य का उदय हुआ है, जिससे रोजगार सहित अनेक उन्नत राष्ट्र-निर्माण के अवसर सृजित होंगे। सीईटीए की संकल्पना आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अन्य देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों के अनुरूप ही है। यह मोदी सरकार की भारत को 2047 तक विकसित बनाने की संकल्पना से जुड़ी रणनीति का एक हिस्सा है। मोदी सरकार ने भारत को तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनाने के अपने संकल्प में नये पंखों को जोड़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास को फिर से स्थापित करने तथा इसे भारतीय और विदेशी निवेशकों

के लिए आकर्षक बनाने के लिए एक दृढ़ रणनीति अपनाई है। विकसित देशों के साथ एफटीए इस रणनीति के केंद्र में है। ऐसे समझौते व्यापार नीतियों से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करके निवेशकों का विश्वास बढ़ाते हैं। पिछली यूपीए सरकार ने भारत के व्यापारिक दरवाजे प्रतिद्वंद्वी देशों के लिए खोलकर भारतीय व्यवसायों को खतरे में डालने वाला रवैया अपनाया था, लेकिन अतीत की उन बड़ी भूलों को सुधारा जा रहा है, जो नये भारत-विकसित भारत का आधार है।

मोदी के मेड इन इंडिया संकल्प की दृष्टि से यह डील बेहद अहम है। इससे करीब 99 प्रतिशत निर्यात यानी यहां से ब्रिटेन जाने वाली चीजों पर टैरिफ से राहत मिलेगी। इसी तरह ब्रिटेन से आनी वाली चीजें भारत में सस्ती मिल सकेंगी। जिससे आम लोगों को अधिक गुणवत्ता वाला सामान सस्ते में सुलभ होगा और जीवनस्तर में व्यापक सुधार होगा। डील से एक बड़ा फायदा होगा टेक्सटाइल्स, लेदर और इलेक्ट्रॉनिक्स को। इनसे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। अभी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी केवल 2.8 प्रतिशत है, जबकि चीन की 28.8 प्रतिशत। इसी तरह, देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 17 प्रतिशत है और सरकार इसे 25 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहती है। इस तरह की डील से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तर पर प्रदर्शन में सुधार होगा। कृषि सेक्टर को भी उन्नत बनाने एवं अधिक उत्पाद की दृष्टि से व्यापक फायदा होगा। इसके लिए इस समय भारत की बातचीत अमेरिका से भी चल रही है। लेकिन वहां कृषि और डेयरी प्रॉडक्ट्स को लेकर रस्साकशी है। अमेरिका इन दोनों क्षेत्रों में खुली छूट चाहता है, जबकि अपने लोगों के हितों को देखते हुए भारत ऐसा नहीं कर सकता। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार होने से भारत के कृषि उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

# संवैधानिक पद की 'ऊंची कुर्सी' अचानक खाली हो गई

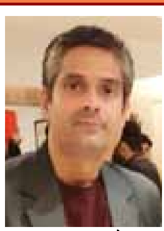

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

**सोमवार, 21 जुलाई को राजनीति में सबसे बड़ा सस्पेंस तब रहा जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। धनखड़ ने खराब स्वास्थ्य बताकर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया लेकिन विपक्ष इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन यह संवैधानिक पद अचानक खाली हो जाना न सिर्फ चौंकाने वाला रहा, बल्कि इसके पीछे छिपे कारणों ने एक बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया है। सत्ता पक्ष जहां चुप्पी साधे है, वहीं विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है। क्या कोई दबाव था? या पर्दे के पीछे चल रही कोई बड़ी राजनीतिक साजिश? इस्तीफे को 'निजी कारण' बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देश इसे इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं। अब सबकी निगाहें इस पर टिक गई हैं कि अगला कदम क्या होगा और क्या यह इस्तीफा सिर्फ एक शुरुआत है 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था।**

देश की राजनीति में दिन सोमवार, 21 जुलाई एक अप्रत्याशित भूचाल तब आया, जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। धनखड़ ने इस्तीफा का कारण अपना खराब स्वास्थ्य बताया और उपराष्ट्रपति पद छोड़ दिया। लेकिन विपक्ष यह कारण मानने के लिए तैयार नहीं है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसी दिन संसद का मानसून सत्र भी शुरू हुआ था। यह सिर्फ एक औपचारिक विदाई नहीं थी, बल्कि सत्ता के शिखर पर बैठी उस संवैधानिक कुर्सी का खाली हो जाना था, जो पूरे देश में संतुलन और गरिमा का प्रतीक मानी जाती है। धनखड़ का यह फैसला न तो पहले से संकेतित था, न ही इसकी कोई राजनीतिक चर्चा सार्वजनिक रूप से हुई थी । यही बात इस घटनाक्रम को एक सस्पेंस थ्रिलर बना गई। सत्ता पक्ष में इसे लेकर गहरा असमंजस है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जहां चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं कई मंत्रियों ने इसे 'निजी कारण' कहकर टालने की कोशिश की। लेकिन पर्दे के पीछे क्या कोई रणनीतिक बदलाव हो रहा है? क्या यह राष्ट्रपति भवन और संसद के बीच किसी बड़ी बदलाव की तैयारी है? ये सवाल अब चर्चा में हैं। वहीं विपक्ष पूरी तरह से हैरान और परेशान है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कोई दबाव था? क्या धनखड़ को कुछ मजबूर किया गया? 'या फिर' क्या यह आने वाले चुनाव से पहले किसी नए समीकरण की बुनियाद है। राजनीतिक गलियारों में एक गूंज सुनाई दे रही है। 'धनखड़ गए तो कौन आएगा?' राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये तीनों

संवैधानिक स्तंभ देश के लोकतंत्र की रीढ़ हैं, और जब इनमें से कोई अचानक हटता है, तो सिर्फ कुर्सी नहीं, पूरा संतुलन डगमगा जाता है। इस घटनाक्रम ने सत्ता के गलियारों में नई हलचल और मीडिया में एक तफ़ान खड़ा कर दिया है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर पीएम मोदी ने एक्स पर टिवीट कर लिखा कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अब सभी की निगाहें सिर्फ एक ओर हैं। अगला उपराष्ट्रपति कौन? और क्यों इतनी जल्दी कुर्सी खाली हुई।देश में 72 साल के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में धनखड़ पहले ऐसे राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति रहे, जिनके खिलाफ दिसंबर 2024 महाभियोग प्रस्ताव लाया था। जो बाद में तकनीकी कारणों से खारिज हो गया था। विपक्ष धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाता रहा था। विपक्ष का दावा था कि वह सिर्फ विपक्ष की आवाज व उनके सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों को दबाते हैं।

**धनखड़ के अप्रत्याशित इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में उथल-पुथल, विपक्ष भी हैरान**

मानसून सत्र के पहले ही दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर जगदीप धानखड़ ने इस्तीफा दे दिया। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट का सहयोग के लिए धन्यवाद भी किया। धनखड़ के इस्तीफे के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार से सवाल करना शुरू कर दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में कहा- इस अप्रत्याशित इस्तीफे में जो दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा है। पीएम मोदी धनखड़ को मन बदलने के लिए मनाएं। यह राष्ट्रहित में होगा। खासतौर पर कृषक समुदाय को बहुत राहत मिलेगी। इस्तीफा के बाद धनखड़ ने खराब स्वास्थ्य का कारण बताया लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं हो रहा है। सोमवार रात देश की राजनीति उस वक्त चौंक गई जब उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। इस अप्रत्याशित फैसले के बाद विपक्षी दलों में हलचल मच गई है। कई नेताओं ने इसे 'अकल्पनीय और चौंकाने वाला कदम' बताते हुए सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है। इस्तीफे की वजहों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, जबकि राष्ट्रपति भवन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अप्रत्याशित इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में उथल-पुथल मची है। विपक्षी दलों ने इसे 'संविधानिक संकट की आहट' बताते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं। कई नेताओं ने मीडिया से बातचीत में नाराजगी और आशंका जाहिर की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा यह सिर्फ इस्तीफा नहीं है, यह किसी बड़े दबाव या असहमति का संकेत है। प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है? पश्चिम बंगाल की मुखमंत्री ममता बनर्जी ने कहा अगर उपराष्ट्रपति खुद को असहज महसूस

## उपराष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा, सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी तैयार

देश में इन दिनों मानसून सत्र चल रहा है। इसके साथ नए उपराष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेताओं की भी निगाहें लगी हुई है। वहीं चार दिन बाद जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद क्या कारण रहे, कोई नहीं समझ पा रहा है। धनखड़ के इस्तीफा को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। खैर यह तो राजनीति का विषय है! अब आइए जानते हैं कि देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे। धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद कई नेताओं के उपराष्ट्रपति बनने को लेकर नाम चर्चाओं में जारी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का नाम ने उपराष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल है। इसी कड़ी में दो नाम और जुड़ गए हैं जो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ वर्तमान में राज्यपाल की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इन दोनों राज्यपालों के नाम हैं ओम माथुर और थावरचंद गहलोत। यह दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गुड लिस्ट में भी है। हालांकि यह भी सच है कि पीएम मोदी और शाह के युग को कोई समझ नहीं पाया है। हाल के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे को सामने लाकर ऐनमौके पर चौंकाती भी रही है। वहीं दूसरी ओर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के 3 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग ने इस पद के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। चुनाव की तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी। इस बीच, भाजपा इस पद के लिए अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना सकती है। फिलहाल जिन नामों पर पार्टी में विचार चल रहा है, उनमें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अन्य नाम सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का भी है। आयोग की तैयारियों के बीच भाजपा की कोशिश होगी कि इस पद का उम्मीदवार किसी अन्य सहयोगी को बनाने की जगह अपने उम्मीदवार का नाम तय कर उसके नाम पर सहयोगी दलों को राजी करे। उपराष्ट्रपति के लिए विपक्ष भी एक मजबूत कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर चुका है। हालांकि अभी तक विपक्ष को उपराष्ट्रपति कौन होगा नाम घोषित नहीं किया है। उम्मीद की जानी चाहिए अगले कुछ दिनों में उपराष्ट्रपति का नाम सामने आ जाएगा। बता दें कि भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रविधान नहीं है। हालांकि, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, इसलिए वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह उनकी अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कर रहे हैं।

करते हैं तो यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। यह बेहद चिंताजनक है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या अब संवैधानिक पद भी सुरक्षित नहीं हैं? यह इस्तीफा अपने आप में एक राजनीतिक संदेश है। राहुल गांधी ने कहा कि धनखड़ जी का इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य का कारण नहीं हो सकता। यह लोकतंत्र की रीढ़ को हिलाने वाली घटना है। प्रधानमंत्री की चुप्पी इस पर और गहरा संदेह खड़ा करती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अचानक इस्तीफा चौंकाने वाला है। यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है। 'डाल में कुछ काला' है, जिसे सरकार छिपा रही है। जयराम रमेश ने कहा कि व्यक्तिगत कारण बताकर इतना बड़ा संवैधानिक फैसला नहीं लिया जाता। यह देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला है। राजस्थान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धनखड़ जी पर पार्टी के भीतर से दबाव था। ये इस्तीफा उनकी निजी इच्छा नहीं, राजनीतिक मजबूरी थी। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि क्या धनखड़ जी की न्यायपालिका के समर्थन वाली टिप्पणियां भाजपा को असहज कर रही थीं? यही इस्तीफे का असली कारण हो सकता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इतने ऊंचे संवैधानिक पद से यूं अचानक हट जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। यह भाजपा के भीतर मतभेद का संकेत है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश को जानने का हक है कि उपराष्ट्रपति ने अचानक पद क्यों छोड़ा। सिर्फ स्वास्थ्य बताकर नहीं टाला जा सकता। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार को पारदर्शिता दिखानी चाहिए। संवैधानिक पद से इस्तीफा सामान्य घटना नहीं होती। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि धनखड़ जी का इस्तीफा पर्दे के पीछे चल रहे किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का संकेत है। सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि संसद और जनता को ये जानने का हक है कि आखिर इस्तीफे की असली वजह क्या है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि संवैधानिक मर्यादाएं खतरे में हैं। अगर उपराष्ट्रपति जैसे पद से व्यक्ति इस्तीफा देता है, तो यह सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा श्री धनखड़ का इस्तीफा यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वर्तमान शासन में स्वतंत्र संस्थाएं बची हैं? एनसीपी नेता ने शरद पवार ने कहा कि संवैधानिक पदों की गरिमा बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। यह इस्तीफा दर्शाता है कि भीतर ही भीतर

बहुत कुछ गलत हो रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा देश के लोकतंत्र की रीढ़ हिल रही है। अब जनता को सच्चाई से रूबरू कराया जाना चाहिए। सीपीआई नेता डी राजा ने भी बयान जारी कर कहा कि यह इस्तीफा दिखाता है कि संवैधानिक पदधारी भी अब स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने धनखड़ को देशभक्त बताया। उन्होंने कहा- धनखड़ ने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, इसलिए इसे स्वीकार किया जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस पर आगे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। सिब्बल ने कहा- मैं व्यक्तिगत रूप से उनके इस्तीफे से खुश नहीं हूं, क्योंकि मैं अब जब संसद जाऊंगा तो उनसे नहीं मिलूंगा। निजीतौर पर मुझे अच्छा नहीं लगा।

**उपराष्ट्रपति का खाली पद संविधान के अनुसार छह महीने के भीतर भरना आवश्यक**

उपराष्ट्रपति पद के लिए संविधान के अनुसार रिक्त पद को छह महीने के भीतर भरना आवश्यक है लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसी कोई निश्चित समय-सीमा नहीं है। केवल यह आवश्यक है कि पद रिक्त होने के बाद यथाशीघ्र चुनाव कराए जाएं। चुनाव आयोग कार्यक्रम की घोषणा करेगा। यह चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के तहत होता है। परंपरा के अनुसार, संसद के किसी भी सदन के महासचिव को बारी-बारी से निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। ये चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि जगदीप धनखड़ ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, लेकिन नया उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने की तिथि से पूरे पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा न कि केवल धनखड़ का शेष कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों और मनोनीत सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत, इसमें राज्य विधानसभाएं भाग नहीं लेतीं। यह चुनाव संसद भवन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक सांसद उम्मीदवारों को वरीयता क्रम के हिसाब से वोट डालता है। निर्वाचित होने के लिए, किसी उम्मीदवार को न्यूनतम आवश्यक मतों की संख्या प्राप्त करनी होती है, जिसे कोटा कहा जाता है। इसकी गणना कुल वैध मतों की संख्या को दो से विभाजित करके और एक जोड़कर की जाती है। यदि पहले चरण में कोई भी उम्मीदवार कोटा पार नहीं करता है, तो सबसे कम प्रथम वरीयता वाले मत पाने वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है, और उनके मत द्वितीय वरीयता के आधार पर शेष उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि एक उम्मीदवार कोटा पार नहीं कर लेता। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए और किसी भी संसदीय क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। उन्हें राष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री जैसे पदों को छोड़कर, केंद्र या राज्य सरकारों के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वहीं निर्वाचन आयोग ने देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। आयोग ने राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को इसके लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिया। इसके साथ ही दो सहायक निर्वाचन अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। निर्वाचन आयोग ने यह नियुक्तियां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के तहत की है और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी अगले कुछ दिन में कर दी जाएगी।

# भारत और मालदीव के रिश्ते फिर पटरी पर

**प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा ने भारत-मालदीव संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। लंबे समय से चले आ रहे तनाव और कूटनीतिक उतार-चढ़ाव के बाद यह यात्रा दोनों देशों के बीच विश्वास की बहाली का प्रतीक बनकर उभरी है। मालदीव की राजधानी माले में प्रधानमंत्री मोदी का जिस गर्मजोशी और भव्यता के साथ स्वागत किया गया, उसने स्पष्ट संकेत दिया कि राष्ट्रपति मुहम्मद मुइज्जु अब रिश्तों की नई राह पर आगे बढ़ने के इच्छुक हैं। राष्ट्रपति मुइज्जु, जो अपने चुनावी अभियान के दौरान 'इंडिया आउट' जैसे नारों के कारण भारत से दूरी बना चुके थे, अब बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से भारत के महत्व को पुन समझते दिखाई दे रहे हैं। शंभू नाथ गौतम**

भारत और मालदीव के बीच हालिया महीनों में पैदा हुए तनाव को पीछे छोड़ते हुए दोनों देशों के संबंधों में अब एक नई गर्माहट आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय (25, 26 जुलाई) मालदीव यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम देने का काम किया। मालदीव की राजधानी माले पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति मुहम्मद मुइज्जु ने पारंपरिक रीति-रिवाजों और राजकीय सम्मान के साथ भव्य स्वागत किया। यह यात्रा विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राष्ट्रपति मुइज्जु के सत्ता में आने के बाद भारत और मालदीव के रिश्तों में ठंडापन आ गया था। चुनावी प्रचार के दौरान मुइज्जु की 'इंडिया आउट' नीति और भारतीय सेना की उपस्थिति को लेकर किए गए बयान तनाव का कारण बने थे। अब मालदीव भारत के साथ अपने रिश्तों को पुनः सशक्त और संतुलित बनाना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुइज्जु के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र शामिल रहे। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। मालदीव ने भारत की 'पड़ोसी प्रथम नीति' की सराहना की और दोनों देशों ने संयुक्त रूप से यह संदेश दिया कि क्षेत्रीय सहयोग ही एशिया-प्रशांत क्षेत्र की प्रगति की कुंजी है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के छात्रों और भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, भारत और मालदीव केवल भौगोलिक पड़ोसी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक रूप से भी जुड़े हैं। उन्होंने द्वीपीय देशों के लिए भारत की मदद की प्रतिबद्धता को दोहराया और नई योजनाओं की घोषण ा भी की जिनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जल आपूर्ति और डिजिटल सहयोग प्रमुख हैं। प्रध ानमंत्री मोदी की यह यात्रा चीन के बढ़ते प्रभाव की पृष्ठभूमि में भी रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। मालदीव की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए भारत वहां स्थायित्व और मित्रता बनाए रखने को लेकर सजग है। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत द्विपक्षीय संबंधों को केवल आर्थिक या राजनीतिक सीमाओं में नहीं देखता, बल्कि उसे दीर्घकालिक साझेदारी के रूप में मानता है। राष्ट्रपति मुइज्जु द्व ारा प्रधानमंत्री मोदी का जिस सद्भाव और भव्यता से स्वागत किया गया, वह इस बात का संकेत है कि अतीत की कड़वाहट को भुलाकर दोनों देश एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। दोनों देशों के बीच अब एक बार फिर आशा, सहयोग और भरोसे की बुनियाद पर रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव यात्रा न केवल कूटनीतिक रूप से महत्वपूण र्ा रही, बल्कि उसने यह भी सिद्ध किया कि संवाद और सहयोग से किसी भी तनाव को खत्म किया जा सकता है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और मालदीव का एक साथ आना न केवल क्षेत्रीय, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी शुभ संकेत है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुइज्जू के बीच कर्ज,

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मत्स्य पालन और वॉटर कृषि, डिजिटल परिवर्तन, फार्माकॉपिया और यूपीआई समेत कुल 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी और मुइज्जू ने माले में रक्षा मंत्रालय के नए भवन का उद्घाटन भी किया। भारतीय पीएम ने मालदीव को 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत एक पौधा गिफ्ट किया।

**बीते कुछ सालों में भारत-मालदीव के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे**

बीते कुछ सालों में भारत-मालदीव के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 2023 में मुइज्जू ने 'इंडिया आउट' नारे के साथ चुनाव जीता था, लेकिन दिसंबर 2023 में दुबई में यूएन कॉप-28 सम्मेलन में पीएम मोदी और मुइज्जू की मुलाकात ने रिश्तों में सुधार की शुरुआत की। दोनों नेताओं ने आर्थिक साझेदारी और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर सहमति जताई। हालांकि, 2024 की शुरुआत में मालदीव के कुछ मंत्रियों की पीएम मोदी और लक्षद्वीप यात्रा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के बाद भारत में 'बायकॉट मालदीव' कैंपेन शुरू हुआ। जनवरी 2024 में मुइज्जू ने चीन यात्रा के बाद कहा कि मालदीव एक छोटा देश हो सकता है, लेकिन कोई इसे 'धमका' नहीं सकता। उन्होंने मई 2024 तक भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाने की मांग की थी, जिसके बाद भारत ने सैनिकों को हटाकर उनकी जगह तकनीकी कर्मचारी भेजे। भारत और मालदीव के साझेदारी कई मायनों में अहम है। खासकर जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया के तटीय देशों के डूबने का खतरा बढ़ रहा है। इसी संकट का सामना मालदीव को भी करना पड़ रहा है। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही चलती रही, तो 2050 तक मालदीव का 80: हिस्सा रहने लायक नहीं बचेगा, और 2100 तक ये पूरा देश समुक्त में समा सकता है।

**मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी मुख्य अतिथि बने**

मालदीव ने शनिवार, 26 जुलाई को पूरे राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक उत्साह के साथ अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस ऐतिहासिक मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय रिश्तों और कूटनीतिक मेलजोल का स्पष्ट संकेत है। राष्ट्रपति मुहम्मद मुइज्जु ने माले के प्रतिष्ठित स्वतंत्रता चौक पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। मंच पर दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने एक साथ मालदीव के राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी, जो एकता और सहयोग की प्रतीकात्मक झलक बन गई। इस आयोजन में मालदीव की सेना, पुलिस, स्कूली बच्चों और सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दीं। अपने विशेष संबोधन में प्रधानमंत्री 60 साल पहले मालदीव ने स्वतंत्रता की जो लौ जलाई थी, आज वह लोकतंत्र और विकास के प्रकाश में बदल चुकी है। भारत, अपनी 'पड़ोस प्रथम' नीति के तहत, मालदीव को न केवल निकटतम पड़ोसी, बल्कि घनिष्ठ मित्र मानता है। प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय सहयोग, आपसी विश्वास और साझा समुद्री सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि भारत सदैव मालदीव की संप्रभुता, प्रगति और आत्मनिर्भरता के लिए सहयोगी बना रहेगा। कार्यक्रम में पीएम मोदी की मौजूदगी एक राजनयिक संदेश भी है, खासकर ऐसे समय में जब भारत और मालदीव के रिश्तों में हाल के महीनों में खटास देखी गई थी। लेकिन इस आमंत्रण और समारोह ने संकेत दिया है कि दोनों देशों ने बीते मतभेदों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया है। इस यात्रा के दौरान कई अहम द्विपक्षीय समझौतों पर बातचीत हुई, जिनमें सांस्कृतिक आदान-प्रदान, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, द्वीपीय विकास, रक्षा साझेदारी और पर्यटन को लेकर विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की इस उपस्थिति को मालदीव ने 'गौरवपूर्ण ऐतिहासिक क्षण' बताया। 1887 से लेकर 1965 तक मालदीव की विदेश नीति और रक्षा ब्रिटिश कंट्रोल में थी। 26 जुलाई 1965 को उसे पूर्ण स्वतंत्रता मिली। भारत सबसे पहला देश था जिसने मालदीव को मान्यता दी थी।

**चीन को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए मालदीव हमेशा महत्वपूर्ण रहा**

स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति न केवल मालदीव की जनता के लिए गौरव का विषय बनी, बल्कि इसने एक गहरा राजनयिक संदेश भी प्रसारित किया। विशेषकर चीन को, जो मालदीव सहित भारत के कई पड़ोसियों में अपनी पकड़ मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहा है। भारत के लिए मालदीव का महत्व केवल उसकी भौगोलिक निकटता तक सीमित नहीं है। यह द्वीपीय देश हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है और एशिया-यूरोप के बीच के सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्गों के पास स्थित है। भारत के लगभग 80: ऊर्जा आयात इन्हीं समुद्री मार्गों से होकर आते हैं। ऐसे में मालदीव में राजनीतिक स्थिरता और भारत समर्थक सरकार का बने रहना भारत की समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा रणनीति के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरी ओर, चीन ने पिछले कुछ वर्षों में मालदीव में बंदरगाह, सड़क और बुनियादी ढांचे के नाम पर अपने प्रभाव का जाल फैलाने की कोशिश की है। बीआरआई के तहत भारी कर्ज देकर वह कई छोटे देशों को आर्थिक रूप से नियंत्रित करने की रणनीति अपना रहा है। जिसे रणनीतिक रूप से कहा जाता है। भारत इस रणनीति को लेकर सजग है और उसने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि वह अपने पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए स्थायी और पारदर्शी विकास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव यात्रा इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह ऐसे समय पर हुई है जब दोनों देशों के रिश्तों में पिछले एक वर्ष के दौरान खटास देखी गई थी। राष्ट्रपति मुइज्जु द्वारा भारत से सैन्य सहयोग में कटौती की मांग, और चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर नई दिल्ली में चिंता व्याप्त थी। लेकिन स्वतंत्रता दिवस समारोह में मोदी की उपस्थिति और दोनों नेताओं की बैठकों में हुई सौहार्द्रपूर्ण चर्चा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत और मालदीव दोनों एक-दूसरे की जरूरत और अहमियत को भलीभांति समझते हैं।

यह यात्रा भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति को भी दृढ़ता से दोहराती है जिसमें भारत यह मानता है कि उसका विकास और सुरक्षा अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंधों पर आधारित है। मालदीव में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत का योगदान उल्लेखनीय रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में कई नए समझौते और सहयोग प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई, जो द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करेंगे। भारत के लिए यह केवल कूटनीतिक अवसर नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक निवेश भी है यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिंद महासागर क्षेत्र में संतुलन बना रहे, चीन का एकाधिकार न हो, और भारत के पड़ोसी भारत के साथ अपने भविष्य को अधिक सुरक्षित समझें। प्रधानमंत्री मोदी की यह उपस्थिति चीन के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अपने पड़ोस को लेकर सजग, सक्रिय और प्रतिबद्ध है। इस ऐतिहासिक यात्रा ने यह प्रमाणित किया कि राजनीति में स्थायी दुश्मन नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं, और जब बात क्षेत्रीय शांति, समुद्री सुरक्षा और एशियाई नेतृत्व की हो, तो भारत और मालदीव जैसे देश सहयोग और विश्वास के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं।

# थाईलैंड और कंबोडिया में 'मंदिर' को लेकर खूनी संघर्ष

दक्षिण-पूर्व एशिया एक बार फिर युद्ध के साये में है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच वर्षों से चला आ रहा सूर्य मंदिर विवाद खून-खराबे में तब्दील हो चुका है। गुरुवार को दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर हुई भीषण गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण यह मंदिर विवाद की वह चिंगारी बन गया है, जिसने पूरे क्षेत्र को तनाव की आग में झोंक दिया है। सीमावर्ती गांव खाली कराए जा रहे हैं, सेना हाई अलर्ट पर है, और दोनों देशों में राष्ट्रवाद की लहर ऊफान पर है। थाईलैंड ने सीमा पर हुई घटनाओं के बाद कंबोडिया का राजदूत निष्कासित किया और अपना राजदूत वापस बुला लिया। जवाब में कंबोडिया ने थाई राजदूत को वापस बुलाया और दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों को निवारक स्तर तक घटा दिया। यह टकराव अब सिर्फ जमीन या धरोहर का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता और संप्रभुता की लड़ाई बन चुका है और दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या यह तनाव एक पूर्ण युद्ध का रूप ले लेगा। दिव्य हिमगिरि की रिपोर्ट।

एशिया के दो देश थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग जैसे हालात बनते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच वर्षों से हिंदू मंदिर प्रेआ विहेयर को लेकर विवाद चला रहा है। पिछले दिनों थाईलैंड ने कंबोडिया पर भीषण हवाई हमला भी किया है। थाईलैंड और कंबोडियाई सैनिकों के बीच सीमा पर एक बड़ी झड़प हुई जिसमें 14 लोग मारे गए, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। दोनों पक्षों ने छोटे हथियारों, तोपों और रॉकेटों से गोलीबारी की, और थाईलैंड ने हवाई हमले भी किए। दोनों देशों की सेनाओं ने छोटे हथियारों, तोपों और रॉकेटों से भारी गोलाबारी की। कंबोडियाई रॉकेट से हमला किया, जिसमें पेट्रोल स्टेशन समेत अन्य नागरिक क्षेत्र प्रभावित हुए।

थाईलैंड ने एफ.16 लड़ाकू जेट्स का उपयोग कर कंबोडिया में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। थाई सेना ने कहा कि उसने गुरुवार को कंबोडिया में जमीनी सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जबकि कंबोडिया ने कहा कि थाई जेट विमानों ने प्राचीन प्रीह विहार मंदिर के पास एक सड़क पर बम गिराए। थाई रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सुरसंत कोंगसिरी ने कहा कि सीमा पर कम से कम छह क्षेत्रों में झड़पें जारी हैं। पहली झड़प गुरुवार सुबह थाईलैंड के सुरीन प्रांत और कंबोडिया के ओद्दार मीनची प्रांत की सीमा पर प्राचीन ता मुएन थॉम मंदिर के पास एक इलाके में हुई। संकटग्रस्त स्थिति के कारण लगभग 40,000 थाई नागरिकों को सीमा से दूर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। अधिकांश लोग 86 गांवों से निकाले गए और अस्थायी निकासी केंद्रों में शरण ली गई। थाईलैंड ने सीमा पर हुई घटनाओं के बाद कंबोडिया का राजदूत निष्कासित किया और अपना राजदूत वापस बुला लिया। जवाब में कंबोडिया ने थाई राजदूत को वापस बुलाया और दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों को निवारक स्तर तक घटा दिया। यह पहली बार नहीं है, जब दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ा हो, लेकिन इस बार यह प्रतिक्रिया अधिक आक्रामक और योजनाबद्ध दिखाई देती है। थाई सेना का दावा है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है, जबकि कंबोडिया ने इसे क्रूर और बर्बर सैन्य आक्रमण करार दिया है। थाईलैंड का दावा है कि हाल ही में बनाई गई बारूदी सुरंगों ने उसके सैनिकों को

घायल किया, जबकि कंबोडिया का कहना है कि यह पुरानी सुरंगों के विस्फोट थे। इस आरोप-प्रत्यारोप से स्थिति और गंभीर होती जा रही है क्योंकि बारूदी सुरंगें न केवल सैनिकों बल्कि स्थानीय नागरिकों के लिए भी एक दीर्घकालिक खतरा बन सकती हैं।

**दोनों देशों के बीच प्रसिद्ध हिंदू मंदिर प्रीह विहार को लेकर चला आ रहा विवाद**

यह विवाद कोई नया नहीं है। दोनों देशों के बीच यह तनाव 12वीं सदी के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर प्रेआ विहेयर को लेकर दशकों से जारी है। प्रेआ विहेयर मंदिर जिसे हिंदी में अक्सर सूर्य मंदिर कहा जाता है, 11वीं सदी में खमेर साम्राज्य द्वारा भगवान शिव को समर्पित कर बनाया गया था। यह मंदिर कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जिससे दोनों देश इस पर अपना दावा करते रहे हैं। 1962 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इस मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा घोषित किया था, लेकिन थाईलैंड के कुछ राष्ट्रवादी गुट इसे आज भी चुनौती देते हैं। मंदिर का न केवल ऐतिहासिक महत्व है, बल्कि कंबोडियाई राष्ट्रीयता और धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ा है। इसी क्षेत्र में बार-बार सैन्य झड़पें हुई हैं। इससे पहले साल 2008, 2011 और अब 2025 में फिर से लड़ाई हो गई थी। मई के बाद से इन दो दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसियों के बीच संबंधा तेजी से खराब हो गए हैं। मई में सीमा पर मौजूद एक क्षेत्र को लेकर झड़प हुआ जिसे दोनों अपना मानते हैं। इसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। कंबोडिया और थाईलैंड एक दूसरे के साथ 817 किलोमीटर की भूमि सीमा (लैंड बॉर्डर) शेयर करते हैं। लेकिन इस भूमि सीमा का मानचित्र बड़े पैमाने पर फ्रांस द्वारा बनाया गया था जब उसने 1863 से 1953 तक कंबोडिया पर राज किया था। 1907 में बना यह नक्शा थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक प्राकृतिक जलक्षेत्र रेखा का पालन करने के समझौते पर आधारित था। लेकिन थाईलैंड ने बाद में इस तथ्य पर मानचित्र का विरोध किया कि इसमें 11वीं शताब्दी के प्रीआ विहेयर मंदिर को कंबोडियाई क्षेत्र में आने वाले डांगरेक पर्वत में रखा था। यूनेस्को के अनुसार कंबोडिया के मैदान पर हावी पठार के किनारे पर स्थित, प्रेआ विहेयर का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।

# जून 2025 में उत्तराखंड में आपदाओं और दुर्घटनाओं में भारी वृद्धिः एसडीसी फाउंडेशन की उदय रिपोर्ट ने त्वरित नीतिगत कार्रवाई की उठाई मांग

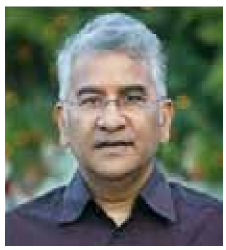

अनुप नौटियाल

देहरादून स्थित पर्यावरणीय एक्शन और एडवोकेसी समूह एसडीसी फाउंडेशन द्वारा जारी उत्तराखंड डिजास्टर एंड एक्सिडेंट एनालिसिस इनिशिएटिव (उदय) की जून 2025 की रिपोर्ट राज्य में आपदाओं और दुर्घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता की गंभीर तस्वीर पेश करती है। प्रतिष्ठित समाचार माध्यमों पर आधारित इस मासिक रिपोर्ट में प्रदेश में आपदाओं, मौसम की अनिश्चितता, खराब सड़कों, कमजोर ढांचागत सुविधाओं और सुरक्षा प्रबंधन की गंभीर खामियों से जुड़ी कई दर्दनाक घटनाएं दर्ज की गई हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, जून माह में राज्य भर में कई बड़ी जानलेवा घटनाएं सामने आईं। 15 जून को केदारनाथ के पास हुई हेलिकॉप्टर दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक दो वर्षीय बच्चा भी शामिल था। इस घटना के बाद चारधाम हेलीकॉप्टर सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गईं और राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। रिपोर्ट में कहा गया है, 'यह हादसा एक बार फिर हिमालयी उड़ानों की सुरक्षा, मौसम प्रोटोकॉल और निगरानी पर सवाल खड़े करता है।'

जून में ही पिथौरागढ़ में 6 जून को एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से छह लोगों की मौत हो गई। वहीं 26 जून को बद्रीनाथ जा रही एक बस अलकनंदा नदी में गिर गई, जिसमें तीन लोगों की मृत्यु और नौ लापता हुए।

मानसून की बारिश ने चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में कई भूस्खलनों को जन्म दिया, जिससे चारधाम यात्रा मार्ग बाधित हुआ और तीर्थयात्रियों व श्रमिकों की जान गई। 28 जून को उत्तरकाशी में बादल फटने के कारण एक श्रमिक शिविर पर भूस्खलन हुआ, जिसमें दो लोगों की मौत और सात लापता हो गए। यमुना नदी में भारी मलवा और अवैधा डंपिंग के चलते स्याना चट्टी के पास एक अस्थायी झील बन गई, जिससे पर्यावरणीय और सुरक्षा संकट और गहराया।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य में 1,100 से अधिक सक्रिय भूस्खलन जोन चिन्हित किए गए हैं। राहत कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 1,270 कर्मी, 489 जेसीबी मशीन, 25 बेली ब्रिज और 482 हेलीपैड तैयार किए गए हैं।

एसडीसी फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल ने कहा, 'अब उत्तराखंड में आपदाएं अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य होती जा रही हैं। उदय रिपोर्ट्स का उद्देश्य इन घटनाओं की मानवीय और पारिस्थितिकीय लागत को सामने लाना है ताकि नीति, प्रशासन और समाज में निर्णायक सुधार हो सके।'

रिपोर्ट राज्य सरकार और संस्थानों से अपील करती है कि वे उत्तराखंड में मजबूत अर्ली वॉर्निंग सिस्टम बनाएं, बुनियादी ढांचे के विकास को नियंत्रित करें, यात्रा मार्गों की सुरक्षा बढ़ाएं और पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें।

# गाती है मल्हार जिंदगी पल पल सावन बरसे!

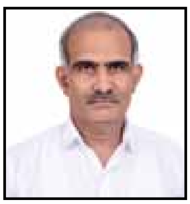

डॉ श्रीगोपाल नारसन
एडवोकेट

***चिंतन का आधार मिले तो, यह जग पावन होता है! गाती है मल्हार जिंदगी, पल-पल सावन होता है!***

प्रसिद्ध साहित्यकार रहे डॉ. योगेंद्रनाथ शर्मा 'अरुण' की ये पंक्तियां आध्यात्मिकता और प्रकृति का ऐसा संगम है, जिसमे से तीज की खुशी झांकती नजर आती है।

हरियाली तीज का पर्व इस वर्ष 27 जुलाई, रविवार को मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 26 जुलाई को रात 10:41 बजे से होगी और यह तिथि 27 जुलाई रात 10:41 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत और पर्व 27 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन एक विशेष संयोग भी बन रहा है- रवि योग, जो 27 जुलाई शाम 4:23 बजे से शुरू होकर 28 जुलाई सुबह 5:40 बजे तक रहेगा। मान्यता है कि रवि योग में किया गया व्रत और पूजन अत्यंत शुभ और फलदायक होता है। हरियाली तीज विशेषकर सुहागिनों द्वारा पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख-शांति के लिए रखा जाता है। हरियाली तीज का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु और स्वयं अखंड सौभाग्यवती बने रहने के लिए भगवान शिव और मां पार्वती का पूजन करती हैं। हरियाली तीज का उपवास सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस तिथि को ही माता पार्वती और भगवान शिव को दोबारा मिलन हुआ था। इसलिए इसे सुखद उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लड़कियां यह उपवास मन वांछित वर की प्राप्ति के लिए रखती है।

हरियाली तीज उपवास पूजा के लिए पीला वस्त्र, केला के पत्ते, जनेऊ, कच्चा सूत, नए वस्त्र, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपड़ा, एक जोड़ी जनेऊ/यज्ञोपवीत भगवान शिव और गणेश जी को चढ़ाए और मां पार्वती को एक हरी साड़ी, सुहाग का 16 श्रृंगार सामान से माता पार्वती की पूजा करे। 16 श्रृंगार में सिंदूर, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, चूड़ियां, महौर, खोल, कुमकुम, कंघी, इत्र आदि शामिल हैं। इसके अलावा, कलश, अक्षत, दूर्वा, तेल, घी, कपूर, अबीर, श्रीफल, चंदन, गाय का दूध, गंगाजल, दही, चीनी, शहद और पंचामृत चीजें भी हरियाली उपवास पूजा के लिए आवश्यक है।

उपवास और पूजा अर्चना के साथ ही सावन मस्ती का महीना भी है। जिसमे तीज पर लड़कियां और महिलाएं झूला भी झूलती है। इसके लिए किसी वृक्ष या गैलरी में झूला डालकर उन्मुक्त हवाओ की सैर करती है। सावन के लोकगीत भी बहुत चर्चित है जिन्हें गाकर भारतीय संस्कृति को जिंदारखने की कोशिश की जाती है। हरियाली तीज पर प्राय: रिमझिम बरसात रहती है। बारिश की फुहारों के साथ सावन के झूले आनन्ददायक बन जाते है। लेकिन अब झूले भी अतीत बनकर रह गए है। सावन के महीने का खास व्यंजन घेवर है। जिसे खाने का अलग ही मजा है। इस माह मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थलों पर भागवत की कथाएं भंडारे होते रहते हैं। विवाहित महिलाएं अपने मायके जाकर यह त्यौहार मनाती हैं तो नवविवाहिताओं को सिंधारा भेजा जाता है। सावन का महीना भगवान शिव की स्तुति का खास अवसर है।सावन माह में प्रकृति भी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। तब हर किसी के मन में उन्मुक्तता की खुशी झलकती हैं। यह आस्था, सौंदर्य और प्रेम का उत्सव है। चारों तरफ हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज कहते हैं। इस अवसर पर महिलाएं झूला झूलती हैं, गाती हैं और खुशियां मनाती हैं। महिलाएं इस दिन 'उमामहेश्वरसायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रतमहं करिष्ये' मंत्र का जाप करती है। इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने पर प्रत्येक स्त्री को वांछित फल मिलता है। भगवान शिव ने पार्वती जी को वरदान दिया था कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेंगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। तीज के अवसर पर विवाहिताए अपने मायके जाना चाहती हैं। एक गीत भी है, 'बहुत दिना हो गए पिया मोय, सावन शुगन मनाऊंगी, भैया आयो मोय लिवावे, मैं पीहर कू जाऊंगी।' वही 'कच्चे नीम की निबौरी, सावन जल्दी अईयो रे, अम्मा दूर मत दीजौ, दादा नहीं बुलावेंगे, भाभी दूर मत दीजौ, भइया नहीं बुलावेंगे।' सावन में खूब गुनगुनाया जाता है। गांव में झूले पर झूलती हुई लड़कियां पेड़ व मुंडेरों पर बैठी हुई चिड़ियों को देखकर अपने मन के भाव को कुछ यूं प्रकट करती हैं, 'पेड़ पै दो चिड़ियां चूं-चूं करती जाएं, वहां से निकले हमारे भइया, क्या-क्या सौदा लाए जी, मां को साड़ी, बाप को पगड़ी और लहरिया लाए जी, बहन की चुनरी भूल आए, सौ-सौ नाम धाराए जी।' सावन के लोकगीत के संवाद भी निराले है, 'हे री काहे की तेरी मात, काहे के तेरे वीर, तू झूले अपने सासरे री।' झूला झूलती महिलाओं में कोई लंबी पीगें बढाती है तो कोई झोंटा देकर उन्हें हवा में उछालती हैं। महिलाएं गाती हैं, 'झूला तो पड़ गए अमुआं की डार पै।' तीज पर राधा-कृष्ण को भी कुछ इस तरह याद किया जाता है, 'आया सावन, बड़ा मन भावन, रिमझिम सी पड़े फुहार, राधा झूल रही कान्हा संग, दिल हुआ बाग बाग। 'सच मे सावन और उसमें भी तीज महिलाओं की खास खुशी व साधना का पर्व है। जिसमे महिलाओं की भक्ति, गायन, उन्मुक्ता साफ झलकती है। यह परंपरा जीवित रहे तभी भारतीय संस्कृति, संस्कार जिंदा रह सकते है।

# स्वास्थ्य जागरूकता पर 'समग्र चिकित्सा संगोष्ठी' का राजभवन में हुआ आयोजन

मंगलवार को राजभवन में हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा 'समग्र चिकित्सा संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस संगोष्ठी में विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों ने समग्र स्वास्थ्य देखभाल के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी प्रदान की। डॉ. रविकांत, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग, एम्स ऋषिकेश ने हृदय रोगों, हाइपरटेंशन के बारे में बताया कि जीवनशैली की गड़बड़ियों के कारण हृदयाघात की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और समय रहते जोखिम कारकों को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है।

डॉ. वी. सत्यावली, विभागाध्यक्ष, मेडिसिन, दून मेडिकल कॉलेज ने मधुमेह और उच्च रक्तचाप से बचाव और इनसे बचने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि आज के युग की 'साइलेंट किलर' बीमारियां हैं जो धीरे-धीरे किडनी फेलियर का कारण बनती हैं। डॉ. गौरव मुखीजा, बाल रोग विशेषज्ञ, दून मेडिकल कॉलेज ने बताया कि बच्चों में एनीमिया का मुख्य कारण पोषक तत्वों की कमी है। उन्होंने कहा कि संतुलित आहार, आयरन-सप्लीमेंटेशन एवं जनजागरूकता आवश्यक है। डॉ. नंदन एस. बिष्ट, आपातकालीन चिकित्सक, दून मेडिकल कॉलेज ने बताया कि आधुनिक जीवनशैली में तनाव एक सामान्य स्थिति बन चुकी है, जो हृदय, मस्तिष्क और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालती है। योग, ध्यान और समय प्रबंधन इसके प्रभावी समाधान हैं।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि यह संगोष्ठी समाज को स्वस्थ रखने की दिशा में एक अहम पहल है। उन्होंने कहा कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप और तनाव आज की जीवनशैली से जुड़ी आम बीमारियाँ बन चुकी हैं, जो बुजुर्गों के साथ-साथ युवाओं को भी प्रभावित कर रही हैं।

राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड की शुद्ध हवा, साफ पानी और शांत वातावरण स्वास्थ्य के लिए अनमोल हैं। लेकिन शहरीकरण, तकनीकी निर्भरता और भागदौड़ वाली दिनचर्या के कारण हमारा रहन-सहन और खान-पान अस्वस्थ हो गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे शांत, प्राकृतिक और आध्यात्मिक राज्य में भी इन बीमारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है, हमें अपनी जीवनशैली पर ध्यान देना होगा। राज्यपाल ने कहा कि हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटना होगा और पारंपरिक आहार, योग, प्राणायाम और स्वस्थ जीवनशैली को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि 'समग्र स्वास्थ्य' का मतलब केवल बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि जीवनशैली, मानसिक शांति, सामाजिक जुड़ाव और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखना भी जरूरी है। उन्होंने उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टरों को जानकारी प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी में विश्वविद्यालय के कई प्रकाशनों का विमोचन राज्यपाल और उपस्थित अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर सचिव राज्यपाल श्री रविनाथ रामन, सचिव श्री दीपक गैरोला, निदेशक एम्स ऋषिकेश प्रो. मीनू सिंह, कुलपति उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रो. अरुण कुमार त्रिपाठी, कुलपति तकनीकी विश्वविद्यालय प्रो. ओंकार सिंह, प्राचार्य दून मेडिकल कॉलेज डॉ. गीता जैन, रजिस्ट्रार डॉ. आशीष उनियाल, निदेशक स्वास्थ्य डॉ. शिखा जंगपांगी सहित राजभवन के अधिकारी एवं कर्मचारी व कालेज के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

# एलयूसीसी फ्रॉड पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से उत्तराखड के सांसदों की भेंट

## एलयूसीसी फ्रॉड मामले में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी: अमित शाह

उत्तराखंड में सामने आए एलयूसीसी फ्रॉड मामले को लेकर आज हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, गढ़वाल सांसद श्री अनिल बलूनी, नैनीताल सांसद श्री अजय भट्ट और टिहरी सांसद महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह जी ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात की।

सांसदों ने उत्तराखंड के हजारों गरीब, ग्रामीण निवेशकों की मेहनत की कमाई को ठगने वाले एलयूसीसी प्रोमोटर्स के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आग्रह किया कि इन अपराधियों को इंटरपोल की मदद से भारत लाकर न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए, ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय और उनकी धनराशि की वापसी सुनिश्चित की जा सके।

सांसदों ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले की जांच की संस्तुति पहले ही कर दी है। इस घोटाले में शामिल लोगों को सख्त सजा दिलाकर भविष्य में इस प्रकार की ठगी को रोका जाना अत्यंत आवश्यक है।

गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इस मामले में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को उनके कृत्य की सजा अवश्य मिलेगी।

यह मामला केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि आम जनता के विश्वास से जुड़ा है, और इसके समाधान के लिए सभी स्तरों पर गंभीर प्रयास किए जाएंगे।

# सीए राजेश्वर पैन्यूली ने पंचायत चुनाव में बड़ी जीत का किया दावा, बोले ऐतिहासिक जीत दर्ज की जाएगी

भाजपा के आर्थिक प्रकोष्ठ सह संयोजक राजेश्वर पैन्यूली ने कहा कि भाजपा के समर्थित प्रत्याशी पंचायत चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने दावा किया कि ब्लाक प्रमुखों के साथ ही पौड़ी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भी भाजपा अपना परचम लहराएगी।

टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र के सीए राजेश्वर पैन्यूली ने पंचायत चुनाव में बड़ी जीत का किया दावा, बोले ऐतिहासिक जीत दर्ज की जाएगी

टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र के जुवा पट्टी में डाबरी, सेल्यूर, कांडीखाल, इंडर आदि, औंण पट्टी में मिश्रवाण गांव-गांव, कफलोग, भेलुंता, देवाल, आदि और भदुरा पट्टी में नौघराल सेमधार, बौसाडी, लिखवार गांव आदि में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार के बाद पत्रकार वार्ता में भाजपा के आर्थिक प्रकोष्ठ सह संयोजक सीए राजेश्वर पैन्यूली ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश बना हुआ है। कहा कि मतदाताओं में भी छोटी सरकार बनाने को लेकर उत्साह बना है। बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर विधानसभा से लेकर ब्लाक व न्याय स्तर पर टीमें काम कर रही है। क्षेत्रों में जाकर प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया जा रहा है। कहा कि प्रदेश सरकार जीरो टॉरलेंस की नीति पर काम कर रही है। भ्रष्ट्राचार के मामले सामने आने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कई जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ भी चुनाव में प्रत्याशियों को मिल रहा है। कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में जुटे हुए है। उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव में भाजपा की भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी।

# जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

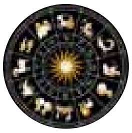
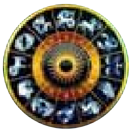

**पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)**
**(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)**

**मेष राशि**- किसी धार्मिक जगह पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। दूसरों की सलाह मानते समय उसके सभी पहलुओं पर अच्छे से सोच-विचार कर लें। किसी बड़े व्यापारी से व्यवसाय में कोई बहुत बड़ी डील होने की संभावना है। प्रेम संबंध भी सही दिशा में रहेंगे। अपने मनोबल को मजबूत बनाए रखें। भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 6

**वृषभ राशि**- किसी भी मुश्किल परिस्थिति में घबराने के बजाय समाधान खोजने का प्रयास करें। लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। इस बेहतरीन ग्रह स्थिति का पूरा फायदा उठाएं। पति-पत्नी के बीच संबंधों में मिठास बनी रहेगी। घर की व्यवस्था भी सही बनी रहेगी। प्रेम प्रसंग मजबूत होंगे। सरल और नियंत्रित व्यवहार रखें। भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 3

**मिथुन राशि**- लोकप्रियता के साथ-साथ लोगों से संपर्क का दायरा भी बढ़ेगा। राजनेताओं से मुलाकात भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। गैर-जरूरी खर्चों में कमी करके आप आर्थिक समस्याओं से बच सकते हैं। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। सोशल मीडिया और बेकार की गतिविधियों में समय बर्बाद न करें। भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 4

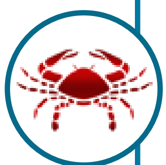

**कर्क राशि**- आप अपने परिवार तथा निजी कार्यों को पहली प्राथमिकता देंगे। घर के बड़े और अनुभवी लोगों की सलाह तथा मार्गदर्शन को भी अपने जीवन में अपनाएं। व्यवसाय से संबंधित किसी नए काम की शुरुआत होगी और जल्दी ही उसके बेहतरीन परिणाम भी सामने आएंगे। पति-पत्नी के बीच सुखद संबंध रहेंगे। भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 3

**सिंह राशि**- आपके आत्मविश्वास के आगे आपके विरोधी टिक नहीं पाएंगे। रुका हुआ या उधार दिया पैसा वसूल करने के लिए अच्छा समय हैं। आपके कुछ करीबी दोस्त या रिश्तेदार ही आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आय के साधान भी बढ़ेंगे। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को हल्के में न लें। भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 8

**कन्या राशि**- आप बहुत ही शांत और सुकून महसूस करेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आस्था बढ़ेगी। अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाए। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें तथा उनके साथ कुछ समय जरूर बिताएं। व्यवसाय संबंधी अपने काम को बहुत ही गंभीरता से पूरा करें। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 2

**तुला राशि**- पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों से भी राहत मिलेगी। अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करें, शारीरिक क्षमता को मजबूत रखें। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जबरदस्त मेहनत की जरूरत है। समय अनुकूल है। पति-पत्नी के संबंधों में मिठास रहेगी जिससे पारिवारिक माहौल सुखद और खुशनुमा बना रहेगा। भाग्यशाली रंग- गुलाबी, भाग्यशाली अंक- 4

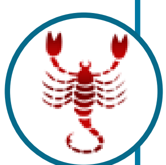

**वृश्चिक राशि**- किसी काम को करने से पहले उसके अच्छे-बुरे पहलुओं पर सोच-विचार कर लें, सफलता मिलेगी। आज किसी भी तरह की यात्रा करने का कोई उचित फायदा नहीं मिलेगा। व्यापार विस्तार संबंधी योजनाओं पर विचार-विमर्श होगा तथा किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। कोई शुभ कार्य संबंधी योजना भी बन सकती है। भाग्यशाली रंग- नारंगी, भाग्यशाली अंक- 5

**धनु राशि**- धार्मिक अथवा आधयात्मिक गतिविधियों में भी रुचि लेने से शांति मिलेगी। पैसा आने के साथ-साथ खर्चे भी होंगे। आज कोर्ट-कचहरी से संबंधित कोई भी मामला टाल दें। कुछ लोग जलन की भावना से आपके प्रति परिवार में कुछ गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। बेहतर होगा कि दूसरों की बातों में न आएं। भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 7

**मकर राशि**- बच्चों का मनोबल बनाए रखने में आपका विशेष प्रयास रहेगा। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाए रखें। विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से भटककर बेकार की बातों में ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से उनके अध्ययन में नुकसान हो सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच चले आ रहे मतभेद दूर होंगे। भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 5

**कुंभ राशि**- विद्यार्थियों को भी प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा में सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। सभी व्यापारिक कार्य अपनी देखरेख में कराएं तथा स्टाफ के साथ भी दोस्ताना व्यवहार रखें। पे व्यवसाय को नई दिशा देगी। ऑफिस में चल रही राजनीति से खुद को दूर ही रखें। व्यायाम और योग पर अवश्य ध्यान दें। भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 4

**मीन राशि**- आपका रहन-सहन तथा बोलने का तरीका दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। अपनी भावुकता जैसी कमजोरियों पर भी काबू पाना जरूरी है, वरना लोग आपका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, तथा काम की क्वालिटी को और बेहतर बनाएं। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। भाग्यशाली रंग- हरा भाग्यशाली अंक- 8

6th DISTF 2025

# SCIENCE AND TECHNOLOGY

## Festival

is coming alive again

**12-14 November, 2025**

Research Innovation Science Technology

विद्यामृतमश्नुते

6th DEHRADUN INTERNATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY FESTIVAL 2025

at

## Vigyan Dham

Uttarakhand Council for Science & Technology
Jhajhra, Dehradun

For more Information Visit us at: www.dehradunsciencefest.org

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

Silkyara™

# हिमालय का वरदान
# बद्री गाय का घी

उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली बद्री गाय जिसको "कामधेनु" भी कहा जाता है, का परंपरागत रूप से बनाया गया घी अब देहरादून में भी उपलब्ध है

- A2 प्रोटीन युक्त
- औषधीय गुणों से भरपूर
- इम्युनिटी बढ़ाने में लाभदायक
- पाचन में हल्का और बाल विकास में सहायक

## कुमार स्वीट्स

- सहस्त्रधारा रोड, निकट क्रॉसिंग
- धर्मपुर, निकट एलआईसी बिल्डिंग

पर उपलब्ध है।

fssai 22623030001586
UDYOG AADHAR MSME UK050061483

**THE DOON HIMALAYAN AGRO FOODS**
Dehradun
Lokesh Asthana - 7409782771